

## राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को 'इंडिया प्राइड गोल्ड अवार्ड'

जयपुर 14 सितम्बर 2010. केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित होटल ताज पैलेस के दरबार हाल में आयोजित भव्य समारोह में 'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम' को विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के लिए 'इंडिया प्राइड गोल्ड अवार्ड-2010' प्रदान किया।

निगम के लिये यह पुरस्कार राजस्थान के ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह एवं विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक डा.एस.के.कल्ला ने ग्रहण किया। समारोह में राज्य के ऊर्जा सचिव श्री नरेश पाल गंगवार भी उपस्थित थे।

भास्कर समूह द्वारा प्रायोजित इंडिया प्राइड अवार्ड-2010 के लिये देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों, उपक्रमों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थी। योजना आयोग के सदस्य और प्रख्यात अर्थशास्त्री डा. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में गठित निर्णायक मंडल ने इलैक्ट्रिसिटी एवं पावर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम को इंडिया प्राइड गोल्ड अवार्ड 2010 के लिये चुना गया।

ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनने वरन् 'विद्युत सरप्लस राज्य' बनने की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार का उपक्रम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम वर्तमान विद्युत संयंत्रों से अधिकतम बिजली उत्पादन करने के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के कार्य में निष्ठा से संलग्न है।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि जुलाई 2000 में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम के गठन के समय विरासत में मिली इसकी क्षमता 1552 मेगावाट थी जिसमें 2545 मेगावाट की वृद्धि करते हुए एक दशक के अल्पकाल में 4097 मेगावाट तक पहुंचा दिया गया है। विद्युत उत्पादन निगम वर्तमान में राज्य की 70 प्रतिशत विद्युत आवश्यकता की पूर्ति करता है। निगम ने 10वीं पंचवर्षीय योजना में 660 मेगावाट के लक्ष्य के विरुद्ध 755 मेगावाट की नई इकाइयां स्थापित की। इसी प्रकार निगम ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1790 मेगावाट के लक्ष्य के विरुद्ध 3150 मेगावाट की इकाइयां स्थापित करने का निश्चय किया जिसमें से 1290 मेगावाट की इकाइयों में उत्पादन आरम्भ हो गया है तथा 1860 मेगावाट की इकाइयों (छबडा में 250, झालावाड में 2X600 व रामगढ में 160 मेगावाट) पर तेजी से चल रहा है जिनसे मार्च 2012 तक विद्युत उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य है।

ऊर्जा मंत्री ने आगे बताया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में निगम 7750 मेगावाट क्षमता की नई इकाइयां स्थापित करेगा जिनमें प्रत्येक 660 मेगावाट की 10 इकाइयां (चार सूरतगढ में तथा दो-दो झालावाड, बांसवाडा व छबडा में) सुपर क्रिटिकल टेक्नोलोजी पर आधारित होगी। इसके अतिरिक्त इसी अवधि में निगम द्वारा प्रत्येक 110 मेगावाट क्षमता की तीन-तीन इकाइयां धौलपुर, कोटा और छबडा में तथा 160 मेगावाट क्षमता की रामगढ में गैस आधारित इकाइयां स्थापित करने का कार्यक्रम है। स्वस्थ पर्यावरण की दृष्टि से सुपर क्रिटिकल तकनीक तथा गैस आधारित इकाइयों का बहुत महत्व है।

निगम को भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ राज्य में पारसा ईस्ट व कांटे बेसन कोयला खदान भी आवंटित की गई है। निगम के 1500 मेगावाट के सूरतगढ, 1240 मेगावाट की कोटा और 500 मेगावाट के छबडा ताप बिजलीघरों से उत्सर्जित फ्लाई ऐश का शत-प्रतिशत उपयोग हो रहा है।